

## उच्च शिक्षा में सुधार - श्रेयस योजना

### संदर्भ

- श्रेयस स्कीम (स्किम फॉर हायर एजुकेशन ऑफ युथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स) के द्वारा भारत सरकार में रोजगार सृजन की ओर बड़ा कदम उठाया है। इस स्कीम के तहत सरकार स्नातक की पढ़ाई के दौरान उस फील्ड में प्रशिक्षण मुहैया कराएगी जिसमें आपकी रुचि है।
- May 2019 से इस योजना को शुरू किया जाएगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर 'श्रेयस (Shreyas)' योजना की शुरुआत की है। इसके साथ ही 'श्रेयस-पोर्टल' की भी शुरुआत की गई है।

### महत्वपूर्ण बिन्दू -

- इस पोर्टल [<http://shreyas.ac.in>] के जरिए स्नातक की पढ़ाई समाप्त करने के बाद छात्र अलग-अलग उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
- गैर-तकनीकी विषयों जैसे बी.ए, बी.कॉम जैसी अन्य डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को नौकरी के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा इस प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी।
- इस योजना का लाभ लेने हेतु शैक्षणिक संस्था को श्रेयस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, छात्र अपने कौशल के अनुसार मीडिया, मैनुफैक्चरिंग, टेलीकॉम, फाइनेंस व बीमा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले सकते हैं।

### इस योजना का लक्ष्य -

- 2022 तक 50 लाख छात्रों को सक्षम बनाकर बेहतर रोजगार प्रदान करना है।
- प्रशिक्षित और कुशल व्यक्तियों का विकास कर रोजगार का सृजन करना।
- उद्योग जगत और सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए चयन
- शिक्षा के साथ रुचि के अनुसार प्रशिक्षण ताकि पढ़ाई के दौरान ही नौकरी के लिए तैयार किया जा सके।
- श्रेयस योजना की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ-साथ कमाई भी कर सकें और उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले लोग प्राप्त हों।

### श्रेयस योजना को दो तरह से लागू किया जाएगा -

1. एड ऑन अप्रेंटिसशिप
2. इंबेडेड अप्रेंटिसशिप (हस्तकौशल)

#### 1. एड ऑन अप्रेंटिसशिप -

- इसके तहत स्नातक के ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जो परीक्षा दे चुके हैं या परीक्षा देने वाले हैं।
- चयनित युवाओं को इंडस्ट्रीज की ओर से ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही हर माह 6 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
- ट्रेनिंग के खत्म होने पर छात्रों की परीक्षा ली जाएगी और सफल छात्रों को कौशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

#### 2. इंबेडेड अप्रेंटिसशिप -

- इसके तहत 6 महीने से 10 महीने तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो जरूरत के हिसाब से तय किया जाएगा।
- इस प्रशिक्षण के दौरान भी छात्रों के 6 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही ट्रेनिंग खत्म होने पर सफल छात्रों को कौशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
- (UGC) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2022 तक उच्च शिक्षा हासिल करने वाले कम से कम 50 फीसदी छात्रों को सही रोजगार मिलने का लक्ष्य तय किया गया है, इस दिशा में श्रेयस (Shreyas) योजना भी महत्वपूर्ण है।
- आजादी के बाद नए भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उच्च शिक्षा का विकास रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा उच्च शिक्षा का विकास हुआ लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ते हुए आज की जरूरतों के हिसाब से शिक्षित और दक्ष करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण चुनौती गुणवत्ता-परक शिक्षा की है।
- यद्यपि भारतीय उच्च शिक्षा विश्व में अपना एक अलग मुकाम रखती है, तथापि इतनी बड़ी जनसंख्या को मानव संसाधन

में तब्दील कर देश के विकास में शामिल करना भी एक चुनौती है।

### भारतीय में उच्च शिक्षा का विकास

- भारत में 1950 में जहां 20 विश्वविद्यालय थे, वही वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संख्या 864 है।
- इनमें 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जबकि 51 राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। जिनमें 16 आईआईटी और 30 एनआईटी शामिल हैं।
- आजादी के बाद से कॉलेजों की संख्या में 74 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में 500 कॉलेज थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 37 हजार है।
- 864 विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थी छात्रों की संख्या 30 करोड़ है।
- मेडिकल कॉलेज 370 हैं।

### उच्च-शिक्षा की चुनौती -

- गुणवत्तापरक और रोजगारपरक शिक्षा की कमी।
- शिक्षा में महिला-पुरुष असमानता भी बड़ी चुनौती है, उच्च शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी 46.2% है, लेकिन कुल श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 27% ही हैं।

### उच्च शिक्षा में सुधार हेतु उपाय -

- सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए वर्ष 2018 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसका उद्देश्य यूजीसी अधिनियम (UGC) को रद्द करना और छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना भी है।
- छात्रों में कौशल विकास हेतु 15 जुलाई 2015 (Skill India) से स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसके लिए अलग से कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया। इस योजना का लक्ष्य कौशल विकास के द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- कौशल विकास और उद्यमिता हेतु 2015 में राष्ट्रीय नीति लागू की गई। यह देश में कौशल विकास हेतु पहला व्यापक नीतिगत ढांचा था।

### प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. श्रेयस योजना का लक्ष्य न केवल स्थानीय कौशल आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि वैश्विक संदर्भ में मानव संसाधन बल को भी प्रदान करना है।
2. जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देने हेतु श्रेयस जैसी योजना प्रासंगिक है।
3. उच्च शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी के अनुरूप श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी पर्याप्त नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) उपर्युक्त सभी

### मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्र. विश्व की बदलती आवश्यकताओं और प्रौद्योगिकियों में हो रहे निरंतर प्रगति के संदर्भ में नव कौशल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस कथन के संदर्भ में श्रेयस, कौशल विकास और स्टैंडअप इण्डिया जैसे सरकार के प्रयास वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर पायेंगे? चर्चा करें।